VOLUME-7, ISSUE-7, JULY-2018 • PRINT ISSN No 2277 - 8160

Original Research Paper

Political Science

सार्क – मुक्त व्यापार के बढ़ते चरण

Dr.Jainifer Patrick Deptt. of Political Science, H.R.P.Degree College,Barkhera Pilibhit.,U.P.,India

ABSTRACT

"दक्षिण एशिया को मुक्त व्यापार क्षेत्र ममें बदलने का सुझाव 1987 को काठमाण्डू शिखर सम्मेलन में रखा गया । इसी उद्देश्य से "साफ्टा" (साउथ एशियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन) का निर्माण किया गया । दक्षिण एशिया क्षेत्र को स्वतन्त्र व्यापार का क्षेत्र बनाने हेतु सभी सार्क सदस्य देशो ने मिलकर "साफ्टा" को लागू करने का विचार किया तथा इसे जनवरी 2006 से लागू करने का निर्णय लिया गया । उदारीकरण की यह प्रक्रिया दो चरणो में लागू होगी । पहले चरण में दो साल में आयात शुल्क कम करके 20 प्रतिशत तक लाना होगा । इसके बाद पांच साल में आयात शुल्क 05 प्रतिशत से कम करना होगा ।"

KEYWORDS :

आठ राष्ट्र, स्पन्दनशील और उभरते हुए प्रजातन्त्र, प्रगतिशील अर्थव्यवस्थाएं और 1.7 विलियन जनसंख्या तथा विश्व के सबसे बड़े धर्मो की जन्मभूमि, दक्षिण एशिया में वह सब विद्यमान है जो इसे वैश्विक परिदृश्य पर अपनी पहचान बनाने वाली एक क्षेत्रीय ताकत बनने के लिए चाहिए । अतः अब समय आ गया है कि बड़ी–बड़ी घोषणाओं और ठोस कार्यवाही के बीच के अन्तर को पाटा जाए ताकि दक्षिण एशिया इस क्षेत्र में और विश्व स्तर पर एक क्षमतावान एवं प्रभावशाली भूमिका का निर्वाह करने वाला क्षेत्र बन सके । आर्थिक संघ में बेहतर व्यापारिक उदारीकरण, सीमापार व्यापार अब संरचना के विकास तथा इस क्षेत्र में माल एवं सेवाओं के मुक्त आवागमन को बाधित करने वाली नॉन–टैरिफ बाधाओं के निवारण की परिकल्पना की गई ।

इसी परिप्रेक्ष्य में 2004 में सार्क के बारहवे शिखर सम्मेलन (इस्लामाबाद) में दो और तीन जनवरी को सार्क देशो की मंत्री स्तरीय बैठक में व्यापार बाधाएं क्रमशः हटाने सम्बन्धी 'साफ्टा' समझौते पर सातो देश के विदेश मंत्रियों ने हस्ताक्षर किये तथा निश्चय किया गया कि क्षेत्र के राज्यों के बीच पूर्ण व्यापार के आयात पर लगने वाले सीमा शुल्क को 2016 तक 0 (शून्य) तक लाना है । साफ्टा समझौता 01 जनवरी 2006 से लागू हो गया और सातो राज्यों के राष्ट्राध्यक्षो ने समझौते का समर्थन किया । समझौते के अनुसार उदारीकरण की प्रक्रिया दो चरणो में लागू होगी । पहले चरण में अधिक विकासशील देश (भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका) को दो साल में सभी वस्तुओं पर आयात शुल्क कम करके 20 प्रतिशत तक लाना होगा । इसके बाद पांच साल में आयात शुल्क 0.5 प्रतिशत से कम करना होगा । न्यूनतम विकासशील देश (बाग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव) को शुल्क में कमी करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जायेगा ।[1]

समझौते में जल्दी प्रतिफल वाले कार्यक्रम के अनुसार भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका को इस क्षेत्र में सबसे कम विकासशील देशो (बाग्लादेश, नेपाल, भूटान) से आने वाले सामान पर अपने सीमाकर को 01 जनवरी 2009 तक 0.5 प्रतिशत तक कम करना है । सबसे कम विकसित देशों को अन्य तरीको से भी लाभ होगा जिनका उल्लेख समझौते में किया गया है ।

2005 में ढाका शिखर सम्मेलन के बाद सेवाओं के व्यापार को भी अध्ययन का विषय बनाया गया और यह साफ्टा की पहल का हिस्सा बन गया । इस सम्बन्ध में 2010 में सोलहवे थिम्पू शिखर सम्मेलन में सेवाओं के व्यापार के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण समझौते "सार्क सेवा व्यापार समझौता" (SATIS) पर हस्ताक्षर हुए ।[2]

सार्क राज्यों का परस्पर व्यापार बढ़ाने के लिए कई द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते भी किये गये जिनमें पारस्परिकता के आधार पर तटकर एवं शुल्क रियायतें तय की गई हैं । श्रीलंका ने भारत तथा पाकिस्तान दोनो से मुक्त व्यापार समझौते किये हैं । इसी प्रकार भूटान और नेपाल ने भी भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते किये हैं । इसी प्रकार साप्टा, साफ्टा एवं द्विपक्षीय व्यापार समझौते आदि अनेक प्रयासों के द्वारा इस क्षेत्र में व्यापार बढ़ाने के प्रयास किये गये हैं ।

भारत ने इस क्षेत्र में मुक्त व्यापार के संबंध में केवल घोषणाएं ही नहीं की वरन् कई कम विकसित छोटे राज्यों के लिए सीमाकर में रियायते भी प्रदान की । 2010 में भारत ने व्यापार की अपनी 744 संवेदनशील वस्तुओं की सूची में से सबसे कम विकसित सार्क राज्यों के लिए 264 वस्तुओं को अलग कर दिया ताकि इन वस्तुओं पर तटकर घटाकर इन राज्यों के साथ व्यापार को बढ़ाया जा सके ।[3] नबम्बर 2011 में सत्रहवें अड्डू (मालदीव) शिखर सम्मेलन के अवसर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह द्वारा सबसे कम विकसित देशों (बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव) हेतु व्यापार में संवेदनशील सूची की वस्तुओं को घटाकर 480 से मात्र 25 कर दिया, अब हटाई गई वस्तुओं पर तटकर नहीं लगेगा ।[4]

इस प्रकार सार्क राज्यों द्वारा इस क्षेत्र में व्यापार बढ़ाने और मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए साप्टा (1993) तथा साफ्टा (2004) समझौते किये; साथ ही कई सदस्य राज्यों द्वारा द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते किये गये और धीरे – धीरे परस्पर सीमाशुल्क रियायते भी प्रदान की गईं । यद्यपि इस क्षेत्र में मुक्त व्यापार के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों का सैद्धान्तिक दृष्टिकोण एवं व्यवहार भिन्न–भिन्न रहा, मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते के क्रियान्वयन में कई बाधाये भी आयी, किन्तु फिर भी कुल मिलाकर आपसी व्यापार बढ़ाने के लिए इन राज्यों के मध्य किये गये उपरोक्त प्रयासो का मिला जुला परिणाम सकारात्मक रुप में सामने आया । उपरोक्त प्रयासो के फलस्वरुप सार्क राज्यों के अन्तःक्षेत्रीय व्यापार में वृद्धि की प्रवृत्तियों का विश्लेषण निम्न बिन्दुओं से स्पष्ट किया जा सकता है –

(1) यद्यपि कुछ सार्क सदस्य राज्यो के मध्य शून्य किन्हीं के बीच कम और कुछ राज्यों के मध्य अधिक व्यापार बढ़ा किन्तु कुल मिलाकर सार्क राज्यों का अन्तःक्षेत्रीय व्यापार बढ़ा है । जहां सार्क राज्यों का आपसी व्यापार वर्ष 2005 में 17493.84 मिलियन डॉलर था ; वहीं यह 2010 में बढ़कर 30578.25 मिनिलयन डॉलर तक पहुँच गया ।[5] इस प्रकार 2005 की तुलना में 2010 में 74.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो सन्तोषजनक मानी जा सकती है ।

(2) इस क्षेत्र में भारत सबसे बड़ा व्यापार का भागीदार रहा है । सार्क सदस्य राज्यो के साथ उसकी व्यापार वृद्धि की स्थिति को निम्न तालिका से स्पष्ट किया जा सकता है ।

India's Trade with SAARC Countries

Country	2005	2006	2007	2008	2009	2010	%age change in Trade in 2010 Compared to 2005
Bangladesh	1766.16	1840.11	2844.43	2870.18	2415.98	3570.24	102.14%
Pakistan	805.61	1471.84	2092.20	1893.13	1723.17	2209.75	174.29%
Nepal	1202.11	1235.80	1908.95	2066.65	41844.40	2375.37	97.60%
Bhutan	187.84	199.71	181.96	262.94	271.97	264.17	40.63%
Sri Lanka	2399.67	2695.25	3273.75	2903.81	2060.85	3018.85	25.80%
Maldives	64.23	71.23	88.22	122.61	110.78	100.89	57.02%
Afganistan	203.93	212.44	322.62	482.58	589.91	711.91	249.09%
Total Trade	6629.55	7726.38	10712.13	10601.90	9017.06	12251.18	84.79%
India'a Total Trade with world	238100.10	297219.00	388800.00	459167.00	422869.00	573693.00	140.94%

Source : IMF Directions of Trade Statistics. Asia Regional Integration Center. Intigration Indicators Database. Arci.adb.org/ indicators. php.

Note : Source of India's Trade with Bhutan is Export-Import Data Department of Commerce. Govt. of India. Commerce .nic.in/eidh/ default. asp.

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारत सार्क राज्यो के साथ व्यापार जहां वर्ष 2005 में 6629.55 मिलियन डॉलर था, वहीं यह 2010 में बढ़कर 12251ण्18 मिलियन डॉलर तक पहुँच गया । इस प्रकार भारत के सार्क राज्यो के साथ व्यापार में 2005 की तुलना में 2010 में 84.79 प्रतिशत वृद्धि हुई । 2005 से 2010 के बीच भारत का सर्वाधिक व्यापार क्रमशः बाग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका के साथ रहा । भारत 2010 में बाग्लादेश के साथ व्यापार सर्वाधिक 3570.24 मिलियन डॉलर; श्रीलंका के साथ 3018.85 मिलियन डॉलर; नेपाल के साथ 2375.37 मिलियन डॉलर रहा ।

इसका प्रमुख कारण इन राज्यों के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते ; साफ्टा समझौते के अनुरुप भारत द्वारा दी गई व्यापार रियायतें, समुचित परिवहन सुविधाएं आदि रहा । इन वर्षो में भारत का भूटान और मालदीव जैसे छोटे सार्क राज्यों के साथ भी व्यापार संतोषजनक रहा ।

(3) भारत के व्यापार की 2005 की तुलना में 2010 में सर्वाधिक वृद्धि प्रतिशत अफगानिस्तान से (249.09 प्रतिशत) फिर पाकिस्तान से (174.29 प्रतिशत) रही । यद्यपि भारत का इन देशो के साथ कुल व्यापार भारत के बाग्लादेश, नेपाल एवं श्रीलंका से व्यापार की तुलना में कम ही रहा है।

(4) कतिपय अपवादो को छोड़कर 2009 में सार्क राज्यो के साथ कुल व्यापार पूर्व वर्ष 2008 की तुलना में कुछ घटा है । इसके पीछे कारण विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की छाया का प्रभाव रहा ।

(5) कुछ सार्क राज्यो के मध्य व्यापार शून्य अथवा नाममात्र का भी रहा है । जैसे नेपाल का अफगानिस्तान और मालदीव से व्यापार शून्य अथवा नाममात्र का रहा है ।

इस प्रकार स्पष्ट हो रहा है कि सार्क राज्यों के बीच कहीं व्यापार पर्याप्त मात्रा बढ़ा है तो कहीं नाममात्र का और किन्हीं राज्यों के बीच घटा है अथवा शून्य भी रहा है ; लेकिन कुल मिलाकर

सार्क राज्यों का आपसी व्यापार वर्ष 2005 की तुलना में 2010 में बढ़ा है ; किन्तु सार्क राज्यों में व्यापार की जितनी क्षमता मौजूद है उसके अनुकूल अभी परिणाम मिलने बाकी हैं । अभी भी इसके सदस्य देशों के बीच आपसी व्यापार सार्क राज्यो द्वारा विश्व के साथ किये जाने वाले व्यापार की तुलना में कम है । 2005 से 2010 के बीच सार्क राज्यों का विश्व के साथ भी व्यापार बढ़ा । 2005 में सार्क राज्यों का विश्व से व्यापार जहां 314113.98 मिलियन डॉलर था ; वहीं वर्ष 2010 में यह दुगुने से अधिक 718504.45 मिलियन डॉलर हो गया ।[6] इस प्रकार 2005 की तुलना में 2010 में सार्क राज्यों का विश्व व्यापार 128.74 प्रतिशत बढ़ा जबकि 2005 की तुलना में 2010 में सार्क राज्यों के आपसी व्यापार में 74.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो सार्क राज्यों के विश्व व्यापार में वृद्धि प्रतिशत से तुलनात्मक रुप से कम है ।

'यूरोपियन यूनियन' तथा 'आसियान' के देशो में जहां अन्तः क्षेत्रीय व्यापार 25 प्रतिशत से अधिक है, वहीं सार्क राज्यों के मध्य परस्पर व्यापार सकल घरेलू उत्पाद के 02 प्रतिशत से कम है । 2004 में साफ्टा समझौते पर हस्ताक्षर करने और उसे लागू करने की सहमति के बाद भी पाकिस्तान के अड़ियल रुख के कारण इस क्षेत्र में अपार क्षमता के बाबजूद व्यापार तेजी से नहीं बढ़ रहा है । भारत व पाकिस्तान के बीच व्यापार की असीम सम्भावनाये हैं । दोनो पक्षो से यदि राजनीतिक सहयोग मिले ; पाकिस्तान अपना रवैया वास्तव में बदले और साफ्टा समझौते के अनुरुप भारत के साथ व्यापार बढ़ाये तो भारत पाकिस्तान के बीच व्यापार 10 मिलियन डॉलर तक बढ़ने की सम्भावना है । साफ्टा समझौते के भलीभांति क्रियान्वित होने से इस क्षेत्र में अन्तः क्षेत्रीय व्यापार 06 विलियन डॉलर से 14 विलियन डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है ।[7]

दक्षिण एशिया में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की दिशा में किये गये साप्टा ;।च्ज्।ए 1993द्ध तथा साफ्टा ;।थ्ज्।द्ध समझौता ;2004द्ध करने से राज्यों में आपसी व्यापार बढ़ा किन्तु अभी 'यूरोपीय यूनियन', आसियान तथा 'उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार संगठन' की भांति 'सार्क' को व्यापार सफलता नहीं मिल पायी है । इसके पीछे कई तत्व उत्तरदायी हैं । इन राज्यों में कई राजनीतिक मुद्दो पर नीतिगत मतभेद हैं; भारत पाकिस्तान में कश्मीर समस्या के कारण मौजूद अविश्वास छोटे राज्यों की संरक्षणवादी नीतियाँ; भारत के आर्थिक प्रभुत्व की स्थापना का भय; सदस्य राज्यों में क्षेत्र से बाहरी बाजारो के लिए प्रतिस्पर्धा, एक ही प्रकार के माल का कई राज्यों द्वारा एक साथ उत्पादन, समुचित यातायात एवं सूचना संपर्क का अभाव; समुचित बैंकिंग सम्बन्धो का अभाव आदि अनेक कारणो से सार्क राज्यों को अभी अन्तःक्षेत्रीय व्यापार में वांछित सफलता नहीं मिल पायी है । यदि सार्क राज्य आपसी मतभेद दूर करके परस्पर विश्वास बहाल करें, संरक्षणवादी नीतियां छोड़कर पारस्परिक लाभ की भावना से क्षेत्र में अधिकाधिक व्यापार करें, बड़े अधिक विकसित राज्य छोटे कम विकसित राज्यों के व्यापारिक हितों का ध्यान रखकर उनको विशेष व्यापार रियायतें देते हुए व्यापार करें, सेवा क्षेत्र में व्यापार समझौता ।ज्ै को भलीभांति लागू करें तो तभी साफ्टा समझौता भलीभांति लागू हो सकेगा और तब ही दक्षिण एशिया आर्थिक समुदाय बनाने का चिरसंकल्पित लक्ष्य भी पूरा हो सकेगा ।

सन्दर्भ–

1. South Asian Free Trade Area – Wikipedia the free Encyclopedia. saarc.sec.org
2. The Time of India, April 30, 2010.
3. S.D. Muni, The Emerging Dimensions of SAARC, Cambridge University Press. New Delhi, 2010, P7
4. Text of Prime Minister Dr. Man Mohan Singh's Speech at Addu (Maldives) 17th SAARC Summit.
5. IMF Directions of Trade Statistics. Asian Regional Integration Center. Integration Indicators. Database.arc.odb.org
6. IMF Directions of Trade Statistics. Asian Regional Integration Center.
7. S.D. Muni, The Emerging Dimensions of SAARC. Cambridge University Press, New Delhi, 2010, P17.